

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	<p>पौष 09, शुक्रवार, ११११ १९४४-दिसम्बर ३०, २०२२ <i>Pausa 09 Friday, Saka 1944- December 30, 2022</i></p>	

भाग ४ (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर २६, २०२२

जी.एस.आर.८५. :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, १९५६ (१९५६ का अधिनियम संख्या ४७) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.२(१)/एफडी/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/२०१७ दिनांक १९-१०-२०२२ का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीश माथूर,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर १९, २०२२

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, २०१२ (२०१२ का अधिनियम सं. २१) की धारा ५५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, २०१३ को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(१) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, २०२२ है।

(२) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. नियम ७५क का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, २०१३ के नियम ७५क के उप-नियम (१) में,-

(i) स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) के अन्त में विद्यमान विराम चिह्न “ । ” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु बीस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाली और हाईटेक परियोजना के रूप में स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस परियोजना से संबंधित असंतुलित बोली के मामले में, अतिरिक्त संपादन प्रतिभूति ली जानी अपेक्षित नहीं होगी।”

[सं.एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.